

न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 60/2020, (फोरलेन)

उनवान

1. रामेन्द्र सिंह वल्द मनमथसिंह शक्तावत मृतक के बजाय—
 - (1) सुशीला कंवर पत्नि रामेन्द्रसिंह शक्तावत निवासी, द्वारिका कॉलोनी, पासल रोड भीलवाड़ा।
 - (2) लोकेन्द्रसिंह पुत्र रामेन्द्रसिंह शक्तावत निवासी, द्वारिका कॉलोनी, पासल रोड भीलवाड़ा।
2. निर्भयसिंह वल्द मनमथसिंह शक्तावत निवासी 18/19 पासल हाउस महावीर कॉलोनी भीलवाड़ा।
3. विजयसिंह वल्द मनमथसिंह शक्तावत निवासी पासल हाउस महावीर कॉलोनी भीलवाड़ा।
4. प्रतापसिंह वल्द मोहनसिंह शक्तावत मृतक के बजाय—
 - (1) सुशीला कंवर पत्नि प्रतापसिंह शक्तावत निवासी पासल तहसील भीलवाड़ा।
 - (2) सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह शक्तावत निवासी पासल तहसील भीलवाड़ा।
 - (3) तेजबहादुर सिंह पुत्र प्रतापसिंह शक्तावत निवासी पासल तहसील भीलवाड़ा।
5. वैभव प्रतापसिंह वल्द अभिमन्युसिंह शक्तावत निवासी शिकार बाडी उदयपुर (राज.)।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।
3. समक्ष अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-3जी-5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध अवार्ड सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाड़ा क्रमांकित/प्रतिकर निर्धारण/390/2018 दिनांक 09.11.2020

प्रकरण संख्या : 65/2020, (फोरलेन)

उनवान

1. मैसर्स पासल होटल एण्ड रिसोर्ट भीलवाड़ा प्रा.लि. रजिस्टर्ड कार्यालय पासल हाउस, कृषि ज्ञान केन्द्र के पास, प्रतापनगर, भीलवाड़ा जरिये अधिकृत प्रतिनिधि दिलीप सिंह पुत्र मोहन सिंह शक्तावत निवासी पासल, तहसील व जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थी

बनाम

1. समक्ष अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) भीलवाड़ा।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-3जी-5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध
अवार्ड सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन) भीलवाड़ा क्रमांकित/प्रतिकर निर्धारण/390/2018 दिनांक 09.11.
2020

उपस्थित -

- 1 अधिवक्ता प्रार्थी- श्री श्यामलाल वैद्य एवं श्री राजेन्द्र सोलंकी
2. अधिवक्ता अप्रार्थी NHA - श्री हरिशचन्द्र शर्मा, श्री विनोद कुमार शर्मा
3. राजकीय अभिभाषक : राजस्थान राज्य एवं सक्षम प्राधिकारी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 13-08-2025

- 1- मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा पारित अवार्ड क्रमांकित/प्रतिकर निर्धारण/390/2018 दिनांक 09.11.2020 के विरुद्ध प्रार्थीगण श्री रामेन्द्र सिंह वगैरहा एवं प्रार्थी मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट भीलवाड़ा प्रा.लि. द्वारा क्रमशः दिनांकित 07-12-2020 एवं 04-12-2020 अन्तर्गत धारा 3 जी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर चुनौति दी गई है। जिनके प्रकरण संख्या क्रमांक 60/2020 एवं 65/2020 इस न्यायालय में कायम हुए हैं। उक्त दोनों प्रकरणों के विवाद बिन्दू समान होने से दोनों प्रकरणों का निर्णय सुविधा के दृष्टिकोण से एक साथ किया जा रहा है।
- 2- श्री रामेन्द्रसिंह वगैरहा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3-जी-5 एनएचएआई एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिये अतिरिक्त भूमि आबादी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3ए(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 31.01.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 24/02/2018 को प्रकाशन कराया गया। इसके उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14/08/2018 को प्रकाशित की गई। जिसके दो स्थानीय समाचार पत्रों में 15-09-2018 को प्रकाशन कराया गया।
- 3- ग्राम पांसल, तहसील भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1833 किस्म गैर मुमकिन आबादी गैर काबिल काश्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर इसमें से 0.0300 हेक्टेयर (300) वर्गमीटर) भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में चौड़ाकरण से प्रभावित होना बताया गया है। इस प्रकार प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त वर्णित अवाप्ताधीन भूमि के क्रम में सक्षम अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाड़ा के द्वारा प्रतिकर निर्धारण किया जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
- 4- उपरोक्त अवाप्तधीन ग्राम पांसल तहसील भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1833 किस्म गैर मुमकिन आबादी में अवस्थित प्रभावित भूमि गढ़ मय मंगरी की पृष्ठ भूमि इस प्रकार है- ग्राम पांसल, तहसील भीलवाड़ा के वर्तमान आराजी नम्बर 1833 किस्म भूमि आबादी है। जिसमें अवाप्त की जाने वाली भूमि मगरी पर गढ़ जो मेवाड रियासत के समय से अवस्थित है, जिसका वर्तमान सर्वे नाप अनुसार 03 तीन बीघा 14 चौदह बिस्वा होता है। ग्राम पांसल, तहसील भीलवाड़ा के वर्तमान आराजी नम्बर 1833 के पुराने (साबिक) आराजी नम्बर 487/1 जो लोक दस्तावेज खसरा पत्रक सेंटलमेंट विभाग द्वारा जारी होने से प्रकट होता है। ग्राम पंचायत पांसल तहसील भीलवाड़ा की साबिक आराजी नम्बर 487/1 में मगरी पर अवस्थित गढ़ को डे-डेस मार्क से दर्शाया गया है। यह मेवाड रियासत, उदयपुर द्वारा ठिकाना पांसल के रेकार्ड में दर्शाया गया है, जो नक्शा साबिक संवत् 1995 सन् 1939 का है।



जसमीत सिंह रांधवा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

- 5- ग्राम पांसल, तहसील भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 487/1 के नवीन आराजी नम्बर 1833 का वर्तमान राजस्व नक्शा जो सन् 1968-69 में मुर्तिय किया गया है। इस नक्शे, पुराने नक्शे में मार्क से दर्शाये जाने के मुताबिक सेंटलमेंट विभाग द्वारा उसकी (गढ़ मय मंगरी) की शकल को नहीं दर्शाया गया है।
- 6- मेवाड रियासत उदयपुर का भारत संघ में विलय सन् 1947 में हुआ था, कि मेवाड रियासत में ठिकाना पांसल के जागिरदार माल (राजस्व) वसूली का कार्य करने के लिये अधिकृत थे, जो कि वंश परम्परा के अनुसार थे। भारत विलय के समय मेवाड रियासत उदयपुर द्वारा अधिकृत अंतिम जागीरदार स्व. मनमथसिंह पिता तेजसिंह शक्तावत थे, जो वर्ष 1978 तक जीवित रहे। जिनके वारिसान् प्रार्थीगण है। स्व. मनमथसिंह जी शक्तावत की वल्लिदयत तेजसिंह होना ग्राम मालोला, तहसील भीलवाडा की सेंटलमेंट विभाग द्वारा जारी नवीन जमावंदी संवत् 2032 पृष्ठ संख्या 180 से प्रमाणित है।
- 7- भू प्रबंध विभाग (सेंटलमेंट विभाग) द्वारा ग्राम पांसल, तहसील भीलवाडा (राज.) की पर्चा खतौनी में नवीन आराजी नम्बर 1833 रकबा 59-13 उन्साठ बीघा तेरह बिस्वा से दर्शाया गया है। जो पर्चा खतौनी लोक दस्तावेज है। मेवाड रियासत उदयपुर का भारत संघ में विलय हो जाने के बाद सन् 1952 में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट 1952 के तहत जागिरी प्रथा समाप्त हो गई और तत्कालीन जागिरदारों से 10,000/- दस हजार से 50,000/- रुपये की वार्षिक माली आय की जागीरें दिनांक 23/08/1954 को राजस्थान सरकार की घोषणा से खालसा (जब्त) जो जागीर एक्ट 1952 की धारा 22 के अनुसार कर ली गई और धारा 23 के तहत वर्णित संपत्तियों पर जागिरदारों का कब्जा माना गया।
- 8- इस संबंध में कलेक्टर भीलवाडा द्वारा दिनांक 25/08/1954 को भूतपूर्व जागिरदार स्व मनमथसिंह को जारी किये गये आदेश क्रमांक 751 है। जो लोक दस्तावेज है। ग्राम पांसल के भूतपूर्व जागिरदार स्व. मनमथसिंह जी के द्वारा दिनांक 25/08/1954 को कलेक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक 751 की पालना में दिनांक 19/02/1955 को जागिर रिज्यूंपशन एक्ट की धारा 23 की अनुपालना में निजी संपत्ति आराजियात खुद काश्त व निजी मकानात् वगैरह की लिस्ट किता 02 आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जिसकी प्राप्ति रसीद जागिर सिगह के क्रमांक 5395 दिनांक 22/02/1955 है। आवेदन पत्र एवं दो प्रत की फेहरिस्त (लिस्ट) लोक दस्तावेज है।
- 9- ग्राम पांसल, तहसील भीलवाडा के भूतपूर्व जागिरदार स्व. मनमथसिंह जी शक्तावत द्वारा दिनांक 26/05/1955 को कलेक्टर, भीलवाडा को प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसमें जागिर रिज्यूंपशन एक्ट की धारा 23 के जैर तहत निजी जायदाद की फेहरिस्त दुबारा पेश करने का वर्णन किया गया और एक प्रति तहसील भीलवाडा को अलग से पेश करने का उल्लेख है। इस आवेदनपत्र के मुखपृष्ठ पर डिप्टी कलेक्टर भीलवाडा द्वारा दिनांक 26/05/1955 को भेजी जाने का उल्लेख है।
- 10- भूतपूर्व जागिरदार स्व. मनमथसिंह के द्वारा तत्कालीन कलेक्टर भीलवाडा के द्वारा जारी आदेश की पालना में आबादी पांसल के उत्तर बाजू कदीमी गढ़ मय मंगरी ज्यों चार भाई बंटों के चार हिस्सो में बटा हुआ होने का उल्लेख है। राजस्व नक्शा मुर्तिबा मेवाड रियासत से " गढ़ मय मंगरी "को डेस डेस से दर्शाया गया है। इससे भूतपूर्व जागिरदार की निजी संपदा होना कलेक्टर भीलवाडा द्वारा माना गया है। जो लोक दस्तोवज है। स्व. मनमथसिंह एवं उनके भाईयों की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण की विरासत में संपदा प्राप्त होना पैतृक संपदा होने से उक्त संपदा के स्वत्वता एवं स्वामित्वता निःसंदेह प्रकट है।
- 11- प्रार्थीगण एवं भाईयों के द्वारा मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट्स लि. को चार रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों से दिनांक 02/02/1999 को भारतीय संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 41 के तहत विक्रय किया जाना निःसंदेह विधि सम्मत है।



अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का कोई विधि सम्मत अधिकार नहीं है।

17-

राजस्व रेकार्ड में जो वर्तमान आराजी नम्बर 1833 है, उसके साबिक नम्बर 487/1 मकबूजा बिलानाम भूमि में अवस्थित "गढ मय मंगरी" को भूतपूर्व जागिरदार को निजी संपत्ति की सूची मुताबिक तत्कालीन राजस्व एजेंसी की लेखन की भूल का खामियाजा भूतपूर्व जागिरदार के वारिसान् को भुगतने को विवश नहीं किया जा सकता है। इस हुई राजस्व रेकार्ड में लेखन की भूल को धारा 67 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के प्रावधान के अनुसार सुधार किया जाना न्यायोचित है।

18-

अवाप्ताधीन भू संपदा का वास्तविक स्वामी (rial owner) या सही सच्चा स्वामी (True owner) कौन है, उक्त संपदा किसके अधिभोग में है। इसकी जाँच पडताल प्रार्थीगण को वैयक्तिक रूप से सम्मानित न करके सिविल न्यायालय की शक्तियां सक्षम अधिकारी में निहित होते हुये उसका पालन नहीं करके त्रुटी कारित की गई है।

19-

सक्षम अधिकारी के द्वारा अपनी विवेकीय शक्तियों का प्रयोग किये बिना तहसीलदार भीलवाडा, विकास अधिकारी सुवाणा एवं विधि परामर्शी के द्वारा जो राय व्यक्त की गई है, वह विधि सम्मत न होकर कानूनी परिधि से बाहर होने से उसी के अनुरूप निर्णय पारित करने में गंभीर रूप से भूल की गई है। इस कारण सक्षम अधिकारी जी का निर्णय दोषपूर्ण है। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार दृश्यमान स्वामी (ostensible Owner) संबंधी कानूनी व्यवस्था व उपबंध का परिपालन नहीं किया गया है।

20-

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में नियम पुराने गृहों के विनियमितीकरण के प्रावधानों को विकास अधिकारी, पंचायत के सरपंच एवं सचिव ने कानूनी व्यवस्था को समझने की भूल ही है, कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं पंचायतीराज नियम 1996 के अनुसार किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा पंचायत द्वारा जारी पट्टे को अविधिमान्य करार नहीं दिया गया है, इसलिये पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख भी इस स्तर पर गैर कानूनी नहीं है। यही नहीं सरपंच, सचिव एवं विकास अधिकारी ने पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों में विहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है, उन्हें अपने ही संकल्प को निरस्त करना अथवा गैर कानूनी या विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया जाना नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार उनके द्वारा गलत टिप्पणी को कानूनी जामा पहनाकर सक्षम अधिकारी ने अपनी क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि की है।



21-

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर सक्षम अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-प्रशासन) भीलवाडा के प्रकरण संख्या एवं 390/18 को निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त अवाप्ताधीन भूमि "गढ मय मंगरी" आराजी नम्बर 1833 में अवस्थित 0.0300 हेक्टेयर (300 वर्ग मीटर) भूमि का प्रतिकर निर्धारण करने हेतु मामले को पुनः रिमांड किया जाने का निवेदन किया गया।

22-

बाद जांच प्रकरण दिनांक 14.12.2020 को पजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी एनएचएआई की ओर से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया जो रेकार्ड पर है। रिकॉर्ड प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने मौजूदा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौडाकरण के लिये अतिरिक्त भूमि आबादी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3ए(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 31.01.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों

में दिनांक 24/02/2018 को प्रकाशन कराया गया। इसके उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14/08/2018 को प्रकाशित की गई।

23-

भू प्रबंध विभाग (सेंटलमेंट विभाग) द्वारा ग्राम पांसल, तहसील भीलवाड़ा (राज.) की पर्चा खतौनी में नवीन आराजी नम्बर 1833 रकबा 59-13 उन्साठ बीघा तेरह बिस्वा से दर्शाया गया है। जो पर्चा खतौनी लोक दस्तावेज है। मेवाड रियासत उदयपुर का भारत संघ में विलय हो जाने के बाद सन् 1952 में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट 1952 के तहत जागीरी प्रथा समाप्त हो गई और तत्कालीन जागिरदारों से 10,000/- दस हजार से 50,000/- रुपये की वार्षिक माली आय की जागीरें दिनांक 23/08/1954 को राजस्थान सरकार की घोषणा से खालसा (जब्त) जो जागीर एक्ट 1952 की धारा 22 के अनुसार कर ली गई और धारा 23 के तहत वर्णित संपत्तियों पर जागिरदारों का कब्जा माना गया।

24-

प्रार्थीगण एवं भाईयों के द्वारा मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट्स लि. को चार रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों से दिनांक 02/02/1999 को भरतीय संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 41 के तहत विक्रय किया जाना निःसंदेह विधि सम्मत् है। उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त पट्टा जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया है, उसे किसी भी कॉम्पीटेंट लीगल ऑथोरिटी द्वारा चैलेंज करके निरस्त नहीं किया गया है। इसलिये इस प्रकरण पर उक्त दस्तावेज को अकारण ही नजरअंदाज किया जाना अनुचित है

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर सक्षम अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-प्रशासन) भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या एवं 390/18 को निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त अवाप्ताधीन भूमि "गढ मय मंगरी" आराजी नम्बर 1833 में अवस्थित 0.0300 हेक्टेयर (300 वर्ग मीटर) भूमि का प्रतिकर निर्धारण करने हेतु मामले को पुनः रिमांड किया जाने का निवेदन किया गया।

25-

विपक्षी एनएचएआई ने मौजूदा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि —“प्रार्थीगण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आप न्यायालय में धारा 3-जी (5) के तहत प्रार्थना पत्र केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, जब अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि किसी पक्षकार को स्वीकार नहीं हो। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम अधिनियम 1956 की धारा 3(जी) (5) के सुसंगत (Relevant) प्रावधान निम्नानुसार है— **3G- Determination of amount payable as compensation- (5) If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-(2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government** सइस प्रकार स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि प्रार्थीगण को स्वीकार नहीं होने पर ही 3 (जी) (5) के प्रावधानों के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजा अभिवृद्धि की प्रार्थना की जा सकती है। परंतु मौजूदा प्रकरण में प्रार्थीगण के हित में कोई राशि अवधारित ही नहीं की गई है अर्थात् कोई भी मुआवजा राशि का अवार्ड प्रार्थीगण के हित में पारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण का हस्तगत प्रकरण विधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं।

26-

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) के अनुसार —

"7- the competent authority or the arbitrator while determining the



powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure] 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters] namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) reception of evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record from any court or office;
- (d) issuing commission for eUamination of witnesses."

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में विकास अधिकारी महोदय से रिपोर्ट मांगे जाने पर उपलब्ध करवायी गयी, जिसमें ग्राम पंचायत पांसल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि तत्कालीन सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये अपने पति व परिवारजनों के हित में गढ़ के अतिरिक्त खाली पड़ी भूमि का भी पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्मित गढ़ का ही किया गया था। तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 47 व 157 के विपरित है। उल्लेखनीय है कि यदि कोई भी पट्टा विधि के प्रावधानों का उल्लघन करते हुये जारी किया जाता है तो वह प्रारम्भ से ही प्रभावहीन व शून्य होता है। इसलिये तत्कालीन सरपंच द्वारा भूमि के संबंध में जारी पट्टा पूर्णतया: अनुचित एवं अवैध होने के कारण शून्यकरणीय है।

36-

विपक्षी एनएचआई का यह भी कथन रहा है कि ग्राम पंचायत समिति सुवाणा की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2020 के अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि पर ग्राम पंचायत ने अपना क्लेम प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि प्रार्थीगण की भूमि नहीं होकर ग्राम पंचायत की भूमि है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.08.2020 में खसरा नम्बर 1833 के संबंध में कोई कथन नहीं है और ना ही उक्त निर्णय दिनांक 21.08.2020 हस्तगत प्रकरण पर चर्चा होता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 पूर्णतया सही एवं उचित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का विकास व रखरखाव ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है व ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के अधीन होती है। आबादी भूमि में खाली पड़ी हुई भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने पर उक्त आबादी भूमि ग्राम पंचायत की भूमि होती है, जिस पर समस्त अधिकार ग्राम पंचायत के होते हैं। खसरा नम्बर 1833 की अवाप्तशुदा भूमि कभी भी प्रार्थीगणों के अधिभोग में नहीं थी। उक्त भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई थी, जिसमें से ही राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गयी है। प्रार्थीगण के पास ऐसा कोई कानूनी ठोस दस्तावेज नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि अवाप्तशुदा भूमि प्रार्थीगण की भूमि है। चूंकि आज भी उक्त भूमि रेवेन्यू रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी खाता संख्या 1 में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में ही आदेश दिनांक 09.11.2020 को पारित किया गया है, जो कि पूर्णतया सही एवं उचित है। ग्राम पंचायत पांसल के द्वारा पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार 2700 वर्गफीट से बाहर जाकर 1,03,840 वर्गफीट का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की अनदेखी करते हुये बिना कब्जेशुदा निवासरत गढ़ के अतिरिक्त खाली पड़ी भूमि का भी जारी कर दिया गया, जबकि आवेदन केवल निर्मित गढ़ का पट्टा प्राप्त करने हेतु ही प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार उक्त पट्टे को चुनौती दी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि उक्त दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है। जबकि प्रार्थीगण के पास उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मालिकाना हक होने के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अवाप्तशुदा भूमि गैर मुमकिन आवादी भूमि होने से ग्राम पंचायत ने मुआवजा प्राप्त करने हेतु अपना क्लेम प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना की गई है वह असत्य एवं गलत होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया है।

38-

प्रार्थीगण एवं विपक्षी एनएचएआई के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने प्रार्थनापत्र एवं जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपने अपने कथनों के समर्थन में अपनी बहस की, जिसे ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद का अध्ययन एवं मनन किया गया। हमारे विनम्र मतानुसार -

प्रार्थीगण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बंध में धारा 3-जी (5) के तहत प्रार्थना पत्र केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, जब अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि किसी पक्षकार को स्वीकार नहीं हो। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम अधिनियम 1956 की धारा 3(जी) (5) के सुसंगत (Relevant) प्रावधान निम्नानुसार है-

3G- Determination of amount payable as compensation- (5) If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-(2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government

उपरोक्त प्रावधानानुसार स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि प्रार्थीगण को स्वीकार नहीं होने पर ही 3 (जी) (5) के प्रावधानों के तहत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की जा सकती है। परंतु प्रकरण में प्रार्थीगण के हित में कोई राशि अवधारित ही नहीं की गई है अर्थात् कोई भी मुआवजा राशि का अवार्ड प्रार्थीगण के हित में पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का मौजूदा प्रार्थनापत्र प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण की ओर से ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 07-12-2020 एवं 04-12-2020 अन्तर्गत धारा-3-जी-5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। अतएव-

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 07-12-2020 एवं 04-12-2020 अन्तर्गत धारा 3-जी-5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को उपरोक्त विवेचन अनुसार खारिज किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा पारित अवार्ड कमांक/प्रतिकर निर्धारण/390/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया जावे। निर्णय की एक अतिरिक्त प्रमाणित प्रति प्रकरण संख्या 65/2020 के साथ भी सलग्न रहें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर (आर्बिटेटर)
जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

